

**सोनल मर्कन्टाइल लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय : 365, यद्वमान प्लाजा, सुतीय तल, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085, दूरभाष : 0111-49091417  
 सीआईएन : L51221DL1985PLC022433, वेबसाइट : www.sonalmmercantile.in, ईमेल आईडी : sonalmmercantile@yahoo.in  
 30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवर्ष के अलेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणाम

(लाख में, इपीएस छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	एकल						समेकित					
		समाप्त तिमाही		समाप्त अर्द्धवर्ष		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही		समाप्त अर्द्धवर्ष		समाप्त वर्ष		
		30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (समाप्त तिमाही)	
1	कुल आय	1005.12	963.88	592.44	1969.00	1161.19	2646.73	1005.12	963.88	592.44	1969.00	1161.19	2646.73
2	कर एवं अपवादिक मदों से पूर्व लाभ	351.44	344.99	247.86	696.43	485.91	1051.62	351.44	344.99	247.86	696.43	485.91	1051.62
3	कर परबन्धन लाभ (आपवादिक मदों के उपरोक्त)	262.86	258.30	185.14	521.15	363.28	784.86	262.86	258.30	185.14	521.15	363.28	784.87
4	कुल व्यापक आय (कर उपरोक्त लाभ/हानि तथा कर उपरोक्त अन्य व्यापक आय से समाविष्ट)	262.86	258.30	185.14	521.15	363.28	784.86	262.86	258.30	185.14	521.15	363.28	784.87
5	प्रदत्त समता अंश पूंजी	1473.85	1473.85	1473.85	1473.85	1473.85	1473.85	1473.85	1473.85	1473.85	1473.85	1473.85	1473.85
6	आय प्रति अंश (रु. 10/- प्रत्येक का प्रति अंश अंकित मूल्य)												
	क) मूलभूत (रु. प्रति अंश)	1.78	1.75	1.26	3.54	2.46	5.33	4.05	3.90	3.09	7.95	6.23	13.93
	ख) तालकीकृत (रु. प्रति अंश)	1.78	1.75	1.26	3.54	2.46	5.33	4.05	3.90	3.09	7.95	6.23	13.93

टिप्पणियाँ :  
 1) उपरोक्त एकल एवं समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमवली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध 30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवर्ष के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, कंपनी की वेबसाइट (www.sonalmmercantile.in) पर तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।  
 2) दिनांक 30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवर्ष के उपरोक्त एकल एवं समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई थी तथा इसका परभाव निदेशक मंडल ने 09 नवंबर 2023 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया।

स्थान : नई दिल्ली  
 दिनांक : 09 नवंबर, 2023

कृपे सोनल मर्कन्टाइल लिमिटेड  
 हस्ता./-  
 विक्रम गोयल  
 पूर्णकालिक निदेशक  
 सीआईएन : 00381116

**नोएडा टेल ब्रिज कंपनी लिमिटेड**

पंजी. कार्यालय : टोल प्लाजा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली-110 091

दूरभाष : 0120-2516495, फैक्स : 0120-2516440

सीआईएन नंबर : L45101DL1996PLC315772, वेबसाइट : www.ntbcl.com, ईमेल : ntbcl@ntbcl.com

**30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम**

क्र. सं.	विवरण	एकल						समेकित					
		समाप्त तिमाही		समाप्त अर्द्धवर्ष		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही		समाप्त अर्द्धवर्ष		समाप्त वर्ष		
		30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (अलेखापरीक्षित)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	परिचालनों से कुल आय	490.80	375.33	789.68	866.13	1,440.41	2,681.83	490.87	375.41	789.95	866.28	1,440.71	2,682.84
II	कारखान पूर्व अवधि हेतु लाभ / (हानि)	(889.11)	(916.62)	(787.15)	(1,805.73)	(1,668.39)	(3,527.51)	(887.20)	(919.14)	(778.81)	(1,806.34)	(1,661.35)	(3,512.90)
III	परिचालनस्त परिचालनों से निवल लाभ / (हानि)	(889.11)	(916.62)	(787.15)	(1,805.73)	(1,668.39)	(3,527.51)	(887.23)	(919.14)	(778.98)	(1,806.37)	(1,661.52)	(3,513.25)
IV	अवधि हेतु कुल अन्य व्यापक आय	0.19	0.29	1.66	0.48	1.19	1.16	0.27	0.38	2.12	0.65	1.73	1.51
V	अवधि हेतु कुल व्यापक आय	(888.92)	(916.33)	(785.49)	(1,805.25)	(1,667.20)	(3,526.35)	(886.96)	(918.76)	(776.86)	(1,805.72)	(1,659.79)	(3,511.74)
VI	प्रदत्त समता अंश पूंजी (रु. 10 का अंकित मूल्य)	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50
VII	आवृत्त (पूर्ववर्ती वर्ष के तुलना-वर्ष में निदर्शितानुसार पुनर्मुल्यांकन आवृत्त छोड़कर)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,003.13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,998.40
VIII	आय प्रति अंश (रु.) मूलभूत तालकीकृत	(0.48) (0.48)	(0.49) (0.49)	(0.42) (0.42)	(0.97) (0.97)	(0.90) (0.90)	(1.89) (1.89)	(0.48) (0.48)	(0.49) (0.49)	(0.42) (0.42)	(0.97) (0.97)	(0.89) (0.89)	(1.89) (1.89)

वित्तीय परिणामों पर टिप्पणियाँ :  
 1) उपरोक्त परिणामों को कंपनी के वित्तीय लेखापरीक्षकों द्वारा एक लेखापरीक्षण के अधीन रखा गया है, लेखापरीक्षण समिति द्वारा इनकी समीक्षा की गई है तथा 9 नवंबर 2023 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है।  
 2) माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर 2016 को अपने निर्णय में 2012 में दायर एक जनहित याचिका (रियायत समझौते की वैधता को चुनौती देनेवाली और रियायत समझौते को अमान्य घोषित करने की मांग करनेवाली) पर कंपनी को शुल्क लगाने और संग्रह करने से संबंधित दो विशेष प्रार्थनाओं को निष्पत्ति मानते हुए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने को बंद करने का निर्देश दिया, लेकिन रियायत समझौते को रद्द करने से इनकार कर दिया। नतीजतन, नोएडा ब्रिज के उपयोगकर्ताओं से उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह 26 अक्टूबर, 2016 से निरन्तरित कर दिया गया है, जिसके खिलाफ कंपनी ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है और उक्त निर्णय पर एक अंतरिम रोक लगाने की मांग की है।  
 दिनांक 11 नवंबर 2016 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक से इनकार करते हुए अपना अंतरिम आदेश जारी किया और यह सत्यापित करने के लिए सीएजी से सहायता मांगी कि क्या रियायत समझौते के संदर्भ में परिपोजना की 'कुल लाभ' कंपनी द्वारा वसूली की गई अथवा नहीं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सीपी डी है और पीठ ने 14 सितंबर, 2018 को निर्देश दिया है कि सीएजी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखा जाए।  
 विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय के लिए लंबित है। कंपनी ने नोएडा को यह भी अधिसूचित किया है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के साथ पठित, रियायत समझौते के तहत 'कानून में बदलाव' का गठन करता है और रियायत समझौते में संशोधन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ताकि कंपनी को काफी हद तक उसी कानूनी, वाणिज्यिक और आर्थिक स्थिति में रखा जा सके जैसे कि यह कानून में उक्त बदलाव से पहले थी। श्रीके नोएडा ने प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की, इसलिए कंपनी ने नोएडा को मध्यस्थता की एक सूचना भेजी थी।  
 मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन किया गया है और कंपनी और नोएडा दोनों ने अपने दावे और प्रतिदावे प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा, नोएडा ने मध्यस्थता कार्यवाहियों को बनाये रखने पर मध्यस्थता और सुलह अभिनियम, 1961 की धारा 16 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसे मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 10 अगस्त, 2018 के आदेश के तहत खारिज कर दिया था।  
 नोएडा ने मध्यस्थता और सुलह अभिनियम, 1961 की धारा 34 के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें 10 अगस्त, 2018 के मध्यस्थ न्यायाधिकरण आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसका निपटारा, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी 2019 को, नोएडा को कोई राहत दिए बिना, कर दिया गया है।  
 नोएडा ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्देश के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिसमें मध्यस्थता कार्यवाहियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। दिनांक 12 अप्रैल, 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता कार्यवाहियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया।  
 दिनांक 31 जनवरी 2020 को कंपनी ने 12 अक्टूबर 2019 के आदेश के तहत दी गई अंतरिम रोक को हटाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। कोविड-19 की महामारी को दृष्टिगत रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई केवल अत्यावश्यक मामलों तक ही सीमित थी। तात्कालिकता पर दाखिल करने के अनुरोध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 21 सितंबर, 2020, 5 अक्टूबर, 2020, 18 नवंबर, 2020, 20 जनवरी, 2021, 16 मार्च, 2021, 15 अप्रैल, 2021, 26 जुलाई, 2021, 10 अगस्त, 2021, 8 सितंबर, 2021 को मामले की सुनवाई की गई और उसके बाद इसे 26 अक्टूबर, 2021 के लिए पोस्ट किया गया।  
 इस बीच, कंपनी को 4 अक्टूबर, 2021 को नोएडा से 30 सितंबर, 2021 की मांग का एक अंतिम नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें नोएडा ने उसकी प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर कंपनी द्वारा देय रु. 26.05 करोड़ की कश्चित मांग उठाई, ऐसा न करने पर नोएडा ने डीएनडी फ्लाइंग के नोएडा स्थल पर लगे सभी विज्ञापन प्रदर्शन हटाने की धमकी दी। उक्त नोटिस प्राप्त होने पर, कंपनी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 4 अक्टूबर, 2021 को एक अंतरिम आवेदन दायर किया। कंपनी द्वारा दायर अत्यावश्यकता/उल्लेख पत्र के आधार पर, मामले को 26 अक्टूबर, 2021 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। नोएडा पर कंपनी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सभी विकास कार्यक्रमों की जानकारी को देने के बावजूद नोएडा के अधिकारियों ने 14 अक्टूबर, 2021 को डीएनडी फ्लाइंग के नोएडा साइट से लगे समस्त विज्ञापन प्रदर्शनों को गैरकानूनी तरीके से हटा दिया।  
 इसके अलावा, 28 अक्टूबर, 2021 को सामग्री की कमी के कारण मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए नहीं लिया गया। कंपनी ने एक बार फिर 28 अक्टूबर, 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप में मामले की तात्कालिकता का उल्लेख किया और मामले को 9 नवंबर, 2021 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था और बाद में 1 दिसंबर, 2021 और 7 दिसंबर, 2021 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था। इसके बाद, 9 दिसंबर, 2021 को मामले का उल्लेख किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर 2021, 6 जनवरी 2022 और 10 जनवरी 2022 को सुनवाई की गई। दिनांक 19 जनवरी 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर 2021 को दायर अंतरिम आवेदन का निपटारा इस निर्देश के साथ किया कि कंपनी को कंपनी द्वारा दायर 2016 की एसएलपी के परिणाम के अधीन, प्रति माह 125 रुपये प्रति वर्ग फीट के अंतिम भुगतान पर आउटडोर विज्ञापन लगाने की अनुमति दी जाएगी।  
 एसएलपी को अंतिम निपटारा के लिए 29 मार्च, 2022 को पोस्ट किया गया था, और उसके बाद 10 मई, 2022, 23 अगस्त, 2022, 18 अक्टूबर, 2022, 2 नवंबर, 2022 और 10 जनवरी, 2023 को पोस्ट किया गया था, लेकिन सभी अवसरों पर समय की कमी के कारण इसे लिया नहीं जा सका। इसके बाद, मामले की सुनवाई 27 जुलाई, 2023 को हुई, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से सीपीजी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की जांच करने और उक्त निष्पत्ति लिखित रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया है और मामले को 25 सितंबर, 2023 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था। दिनांक 25 सितंबर, 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विद्वान पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि प्रतिवादियों को सीएजी रिपोर्टों की एक प्रति प्रदान की गई है और इस प्रकार मामले को 21 नवंबर, 2023 को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।  
 रियायती समझौते (मुआवजे और अन्य उपायों से संबंधित) के प्रावधानों पर निदेशक मंडल द्वारा रखी गई कानूनी राय और निर्मलता के आधार पर, कंपनी को मरोसा है कि अमूर्त और अन्य परिस्थितियों का अंतर्निहित मूल्य शीघ्रता नहीं है।  
 कंपनी प्रोजेक्ट एसेट्स का अनुकरण करने सहित रियायती समझौते के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करना जारी रखती है।  
 दिनांक 20 सितंबर, 2021 को कंपनी को निर्धारित वर्ष 2018-19 के लिए आय कर अभिनियम 1961 की धारा 144बी के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत आय कर विभाग से एक मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें मूल्य को एक राजस्व सहायिकी के रूप में विचारित करके, प्राथमिक रूप में मूल्य के मूल्यांकन के आधार पर रु. 46.23 करोड़ की मांग की गई है।  
 कंपनी ने 30 सितंबर, 2021 को मूल्यांकन अधिकारी से जर्नल कार्रवाई को स्थगित रखने का अनुरोध किया है और उपरोक्त मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध 19 अक्टूबर, 2021 को आय कर आयुक्त (अपील) और राष्ट्रीय फिसेलर अपील केंद्र (एनएफएसी) के समक्ष अपील दायर की है।  
 फिसेलर 2019 के दौरान, कंपनी को आय कर अभिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए एक मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें कर विभाग के साथ ऐतिहासिक विवाद के आधार पर क्रमशः रु. 357 करोड़ रु. 383.48 करोड़ की मांग की गई थी, जो मुख्य रूप से भविष्य में वसूल किए जाने वाले निर्दिष्ट रिटर्न के बकाया, भूमि और अन्य वस्तुओं के मूल्यांकन के संबंध में है। कंपनी ने प्रथम स्तरीय अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष फिसेलर अपील योजना, 2020 के तहत शुरू किये गए अनुसार एक अपील दायर की है, दोनों अपीलों को एनएफएसी में स्थानांतरित कर दिया गया है।  
 कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए एनएफएसी से आय कर अभिनियम 1961 की धारा 270ए के तहत 15 मई 2021 को एक कारण बताओ नोटिस भी प्राप्त हुआ है। हालांकि, कंपनी ने अनुभव किया है कि जर्नलों की कार्यवाहियों को स्थगित रखा जाए क्योंकि मुग-दोषों के आधार पर की जानेवाली अपीलें जो हैं वे वर्तमान में आय कर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित हैं।  
 आय कर विभाग ने, पहले के वर्षों में, रु. 1,340.03 करोड़ की मांग की थी, जो मुख्य रूप में मूल्य आवंटन के संबंध में टोल और राजस्व सहायिकी से भविष्य में वसूल किए जाने वाले निर्दिष्ट रिटर्न के अतिरिक्त बकाया के संबंध में थी। दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से आदेश की प्राप्ति के अनुसार, कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2006-07 से 2014-15 के संदर्भ में मूल्यांकन अधिकारी, आय कर विभाग, नई दिल्ली से मांग का एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जो सीआईटी (ए) के उक्त आदेश को प्रभावी करता है, जिसके द्वारा रु. 10,893.30 करोड़ की अतिरिक्त कर मांग उठाई गई थी और मांग में वृद्धि मुख्यतः भूमि के मूल्यांकन के कारण थी। कंपनी ने आय कर विभाग न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में स्थगन आवेदन के साथ एक अपील दायर की है। इस मामले की सुनवाई आईटीएटी द्वारा 19 दिसंबर 2018 में की गई थी। 21 जनवरी 2019 और 6 फरवरी 2019 को भी 15 अक्टूबर 2018 के निर्देशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी, जो मुख्य रूप से मूल्य आवंटन के संबंध में टोल और राजस्व सहायिकी से भविष्य में वसूल किए जाने वाले निर्दिष्ट रिटर्न के अतिरिक्त बकाया के संबंध में थी। दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से आदेश की प्राप्ति के अनुसार, कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2006-07 से 2014-15 के संदर्भ में मूल्यांकन अधिकारी, आय कर विभाग, नई दिल्ली से मांग का एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जो सीआईटी (ए) के उक्त आदेश को प्रभावी करता है, जिसके द्वारा रु. 10,893.30 करोड़ की अतिरिक्त कर मांग उठाई गई थी और मांग में वृद्धि मुख्यतः भूमि के मूल्यांकन के कारण थी। कंपनी ने आय कर विभाग न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में स्थगन आवेदन के साथ एक अपील दायर की है। इस मामले की सुनवाई आईटीएटी द्वारा 19 दिसंबर 2018 में की गई थी। 21 जनवरी 2019 और 6 फरवरी 2019 को भी 15 अक्टूबर 2018 के निर्देशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी, जो मुख्य रूप से मूल्य आवंटन के संबंध में टोल और राजस्व सहायिकी से भविष्य में वसूल किए जाने वाले निर्दिष्ट रिटर्न के अतिरिक्त बकाया के संबंध में थी। दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से आदेश की प्राप्ति के अनुसार, कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2006-07 से 2014-15 के संदर्भ में मूल्यांकन अधिकारी, आय कर विभाग, नई दिल्ली से मांग का एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जो सीआईटी (ए) के उक्त आदेश को प्रभावी करता है, जिसके द्वारा रु. 10,893.30 करोड़ की अतिरिक्त कर मांग उठाई गई थी और मांग में वृद्धि मुख्यतः भूमि के मूल्यांकन के कारण थी। कंपनी ने आय कर विभाग न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में स्थगन आवेदन के साथ एक अपील दायर की है। इस मामले की सुनवाई आईटीएटी द्वारा 19 दिसंबर 2018 में की गई थी। 21 जनवरी 2019 और 6 फरवरी 2019 को भी 15 अक्टूबर 2018 के निर्देशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी, जो मुख्य रूप से मूल्य आवंटन के संबंध में टोल और राजस्व सहायिकी से भविष्य में वसूल किए जाने वाले निर्दिष्ट रिटर्न के अतिरिक्त बकाया के संबंध में थी। दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से आदेश की प्राप्ति के अनुसार, कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2006-07 से 2014-15 के संदर्भ में मूल्यांकन अधिकारी, आय कर विभाग, नई दिल्ली से मांग का एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जो सीआईटी (ए) के उक्त आदेश को प्रभावी करता है, जिसके द्वारा रु. 10,893.30 करोड़ की अतिरिक्त कर मांग उठाई गई थी और मांग में वृद्धि मुख्यतः भूमि के मूल्यांकन के कारण थी। कंपनी ने आय कर विभाग न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में स्थगन आवेदन के साथ एक अपील दायर की है। इस मामले की सुनवाई आईटीएटी द्वारा 19 दिसंबर 2018 में की गई थी। 21 जनवरी 2019 और 6 फरवरी 2019 को भी 15 अक्टूबर 2018 के निर्देशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी, जो मुख्य रूप से मूल्य आवंटन के संबंध में टोल और राजस्व सहायिकी से भविष्य में वसूल किए जाने वाले निर्दिष्ट रिटर्न के अतिरिक्त बकाया के संबंध में थी। दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से आदेश की प्राप्ति के अनुसार, कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2006-07 से 2014-15 के संदर्भ में मूल्यांकन अधिकारी, आय कर विभाग, नई दिल्ली से मांग का एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जो सीआईटी (ए) के उक्त आदेश को प्रभावी करता है, जिसके द्वारा रु. 10,893.30 करोड़ की अतिरिक्त कर मांग उठाई गई थी और मांग में वृद्धि मुख्यतः भूमि के मूल्यांकन के कारण थी। कंपनी ने आय कर विभाग न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में स्थगन आवेदन के साथ एक अपील दायर की है। इस मामले की सुनवाई आईटीएटी द्वारा 19 दिसंबर 2018 में की गई थी। 21 जनवरी 2019 और 6 फरवरी 2019 को भी 15 अक्टूबर 2018 के निर्देशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी, जो मुख्य रूप से मूल्य आवंटन के संबंध में टोल और राजस्व सहायिकी से भविष्य में वसूल किए जाने वाले निर्दिष्ट रिटर्न के अतिरिक्त बकाया के संबंध में थी। दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से आदेश की प्राप्ति के अनुसार, कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2006-07 से 2014-15 के संदर्भ में मूल्यांकन अधिकारी, आय कर विभाग, नई दिल्ली से मांग का एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जो सीआईटी (ए) के उक्त आदेश को प्रभावी करता है, जिसके द्वारा रु. 10,893.30 करोड़ की अतिरिक्त कर मांग उठाई गई थी और मांग में वृद्धि मुख्यतः भूमि के मूल्यांकन के कारण थी। कंपनी ने आय कर विभाग न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में स्थगन आवेदन के साथ एक अपील दायर की है। इस मामले की सुनवाई आईटीएटी द्वारा 19 दिसंबर 2018 में की गई थी। 21 जनवरी 2019 और 6 फरवरी 2019 को भी 15 अक्टूबर 2018 के निर्देशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी, जो मुख्य रूप से मूल्य आवंटन के संबंध में टोल और राजस्व सहायिकी से भविष्य में वसूल किए जाने वाले निर्दिष्ट रिटर्न के अतिरिक्त बकाया के संबंध में थी। दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से आदेश की प्राप्ति के अनुसार, कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2006-07 से 2014-15 के संदर्भ में मूल्यांकन अधिकारी, आय कर विभाग, नई दिल्ली से मांग का एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जो सीआईटी (ए) के उक्त आदेश को प्रभावी करता है, जिसके द्वारा रु. 10,893.30 करोड़ की अतिरिक्त कर मांग उठाई गई थी और मांग में वृद्धि मुख्यतः भूमि के मूल्यांकन के कारण थी। कंपनी ने आय कर विभाग न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में स्थगन आवेदन के साथ एक अपील दायर की है। इस मामले की सुनवाई आईटीएटी द्वारा 19 दिसंबर 2018 में की गई थी। 21 जनवरी 2019 और 6 फरवरी 2019 को भी 15 अक्टूबर 2018 के निर्देशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी, जो मुख्य रूप से मूल्य आवंटन के संबंध में टोल और राजस्व सहायिकी से भविष्य में वसूल किए जाने वाले निर्दिष्ट रिटर्न के अतिरिक्त बकाया के संबंध में थी। दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से आदेश की प्राप्ति के अनुसार, कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2006-07 से 2014-15 के संदर्भ में मूल्यांकन अधिकारी, आय कर विभाग, नई दिल्ली से मांग का एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जो सीआईटी (ए) के उक्त आदेश को प्रभावी करता है, जिसके द्वारा रु. 10,893.30 करोड़ की अतिरिक्त कर मांग उठाई गई थी और मांग में वृद्धि मुख्यतः भूमि के मूल्यांकन के कारण थी। कंपनी ने आय कर विभाग न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में स्थगन आवेदन के साथ एक अपील दायर की है। इस मामले की सुनवाई आईटीएटी द्वारा 19 दिसंबर 2018 में की गई थी। 21 जनवरी 2019 और 6 फरवरी 2019 को भी 15 अक्टूबर 2018 के निर्देशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी, जो मुख्य रूप से मूल्य आवंटन के संबंध में टोल और राजस्व सहायिकी से भविष्य में वसूल किए जाने वाले निर्दिष्ट रिटर्न के अतिरिक्त बकाया के संबंध में थी। दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से आदेश की प्राप्ति के अनुसार, कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2006-07 से 2014-15 के संदर्भ में मूल्यांकन अधिकारी, आय कर विभाग, नई दिल्ली से मांग का एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जो सीआईटी (ए) के उक्त आदेश को प्रभावी करता है, जिसके द्वारा रु. 10,893.30 करोड़ की अतिरिक्त कर मांग उठाई गई थी और मांग में वृद्धि मुख्यतः भूमि के मूल्यांकन के कारण थी। कंपनी ने आय कर विभाग न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में स्थगन आवेदन के साथ एक अपील दायर की है। इस मामले की सुनवाई आईटीएटी द्वारा 19 दिसंबर 2018 में की गई थी। 21 जनवरी 2019 और 6 फरवरी 2019 को भी 15 अक्टूबर 2018 के निर्देशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी, जो मुख्य रूप से मूल्य आवंटन के संबंध में टोल और राजस्व सहायिकी से भविष्य में वसूल किए जाने वाले निर्दिष्ट रिटर्न के अतिरिक्त बकाया के संबंध में थी। दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से आदेश की प्राप्ति के अनुसार, कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2006-07 से 2014-15 के संदर्भ में मूल्यांकन अधिकारी, आय कर विभाग, नई दिल्ली से मांग का एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जो सीआईटी (ए) के उक्त आदेश को प्रभावी करता है, जिसके द्वारा रु. 10,893.30 करोड़ की अतिरिक्त कर मांग उठाई गई थी और मांग में वृद्धि मुख्यतः भूमि के मूल्यांकन के कारण थी। कंपनी ने आय कर विभाग न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में स्थगन आवेदन के साथ एक अपील दायर की है। इस मामले की सुनवाई आईटीएटी द्वारा 19 दिसंबर 2018 में की गई थी। 21 जनवरी 2019 और 6 फरवरी 2019 को भी 15 अक्टूबर 2018 के निर्देशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी, जो मुख्य रूप से मूल्य आवंटन के संबंध में टोल और राजस्व सहायिकी से भविष्य में वसूल किए जाने वाले निर्दिष्ट रिटर्न के अतिरिक्त बकाया के संबंध में थी। दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से आदेश की प्राप्ति के अनुसार, कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2006-07 से 2014-15 के संदर्भ में मूल्यांकन अधिकारी, आय कर विभाग, नई दिल्ली से मांग का एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जो सीआईटी (ए) के उक्त आदेश को प्रभावी करता है, जिसके द्वारा रु. 10,893.30 करोड़ की अतिरिक्त कर मांग उठा